(b) and (c). A sum of Rs. 5,000 has been sanctioned for the grant of cash relief to deserving victims of the storm. The amount of grant will depend on the circumstances of each case.

T.A. and D.A. to Staff on Election Duty

2349. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government employees who were employed to supervise and conduct the bye-election held in New Delhi in April, 1961 have not yet been paid their Travelling Allowance and Daily Allowance etc. in that connection;

(b) if so, reasons for this delay; and

(c) the date by which the dues are likely to be cleared?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Mishra): (a) No claim for travelling allowance and daily allowance from the Central Government employees employed to supervise and conduct the bye-election held in New Delhi in April, 1961 is pending with the Chief Electroal Officer, Delhi, the authority competent to countersign the relevant bills.

(b) and (c). Do not arise.

Chanderi Fort

2350. { Shri Birendra Bahadur Singh: / Shrimati Jamuna Devi:

Will the Minister of **Scientific Research and Cultural Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government are demolishing the walls of the Chanderi Fort;

(b) whether the Madhya Pradesh Government had obtained the approval of Central Government before taking this step; and

(c) if not, whether Central Government intend asking State Government to stop demolition of the walls?

The Deputy Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Dr. M. M. Das): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the house in due course.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये माल डिब्बे

२३५१. **{ श्री सरजू पाण्डेय : / श्री ज० ब० सिंह :**

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश का उद्योगों के लिये जो प्रदेशीय कोटा पहले २२९९६ वैगन निर्धारित था वह घटा कर २२२६ वैगन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र के पास कोई विरोध-पत्र भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : (क) तथा (ख). पूर्व समय में उपलब्ध रेल परिवहन के मुकाबले पर कोयले का कोटा बहुत अधिक था । यह महसूस किया गया कि यह उपभोक्ताओं के हित में होगा यदि आवंटन इस प्रकार किया जाए; जिसके वास्तविक रूप में परिवहन करने की आशा की जा सकती है । इस उपर्युक्त आवंटन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता लोग अपने यूनिटों के काम करने की योजना को ठीक ढंग से बना सकते हैं । अतः १९६२ के लिये सारे राज्यों के, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कोटे का तदनुसार संशोधन किया गया ताकि वह (कोटा) उपलब्ध रेल-परिवहन क्षमता से निकटतम बराबरी पा सके । उत्तर प्रदेश में राज्य नियन्त्रित अग्रताओं के लिये कोयले के